भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : 1515

गुरुवार, 13 फ़रवरी, 2025/24 माघ, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

हवाई संपर्क में सुधार

1515. श्री पी.सी.मोहन:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ान योजना के तहत बेहतर हवाई संपर्क से टियर-2 और टियर-3 शहरों को लाभ सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) सरकार किस तरीके से बुनियादी ढांचे की चुनौतियों और वित्तीय संधारणीयता का समाधान करती है;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय कैरियर्स की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता पर उड़ान 5.0 और एयर इंडिया-विस्तारा विलय जैसे नीतिगत अपडेट के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विमानन बुनियादी ढांचे के विस्तार को ध्यान में रखते हुए अल्पसेवित क्षेत्रों में छोटे हवाईअड्डों को आवश्यक सुरक्षा, संरक्षा और नौवहन सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय लागू किए जा रहे हैं;

(ङ) सरकार टियर-2 और टियर-3 शहरों में विस्तार योजना को प्रोत्साहित करने के लिए कुशल विमानन पेशेवरों की मांग का किस प्रकार समाधान करती है;

(च) देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में संधारणीयता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गई है; और

(छ) क्या सरकार वैश्विक विमानन केन्द्र के रूप में देश की स्थिति को मजबूत करने और क्षेत्रीय संपर्क को प्रोत्साहित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय भागीदारी की संभावना की तलाश कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोले)

(क) : सरकार ने दिनांक 21-10-2016 को क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) - 'उड़ान' योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य टियर-2 और टियर-3 शहरों में असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों का पुनरुद्धार करके क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सुविधाजनक बनाना/बढ़ाना है, ताकि आम जनता के लिए हवाई यात्रा किफायती हो सके। इस योजना के तहत, 13 हेलीपोटों और 2 वाटर एयरोड्रोमों सहित 88 असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों को जोड़ने वाले 619 आरसीएस मार्गों को प्रचालनरत किया गया है।

(ख) : देश में हवाईअड्डों का विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है। विमानन अवसंरचना में सुधार के लिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और अन्य पीपीपी

हवाईअड्डा प्रचालकों ने हवाई यातायात और यात्री वृद्धि की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए देश में विभिन्न हवाईअड्डों के विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक 91,000 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजीगत व्यय योजना शुरू की है। परियोजनाओं में नए हवाईअड्डे, मौजूदा टर्मिनलों का विस्तार और परिवर्तन, अतिरिक्त यात्री सुविधाएं, नए टर्मिनल, रनवे और एप्रन का विस्तार एवं सुदृढीकरण, तथा नियंत्रण टावर एवं तकनीकी ब्लॉक जैसे एएनएस (एअर नेविगेशन सर्विसेज) कार्य शामिल हैं।

(ग) : एअर इंडिया और विस्तारा के विलय से भारतीय एयरलाइनों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, जैसे:-

- सुदृढ बाजार स्थिति : इस विलय से भारत की सबसे बड़ी पूर्ण-सेवा एयरलाइन बनी है, जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में एअर इंडिया की स्थिति मजबूत हुई है। इससे बेड़े का आकार और मार्ग नेटवर्क बढ़ा है, जिससे एअर इंडिया एक मजबूत वैश्विक प्रतिस्पर्धी बन गई है।

- बेहतर सेवा गुणवत्ता और ब्रांड छवि

- विलय से एअर इंडिया के इन-फ्लाइट अनुभव में भी सुधार हुआ है, जिससे लंबी दूरी के मार्गों पर ग्राहकों को बनाए रखना बेहतर हुआ है।

- विस्तारित अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क: विलय से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में हब का बेहतर उपयोग संभव होगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए पारगमन विकल्प बेहतर होंगे।

- लागत सहक्रिया और बेड़े का आधुनिकीकरण: संयुक्त इकाई को परिचालन लागत में कमी होने के साथ ही अधिक मात्रा के कारण अल्पव्यय का लाभ होगा।

- एअर इंडिया के चालू बेड़े के विस्तार (एअरबस ए350, बोइंग 777, 787) से लंबी दूरी की उड़ानों को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी।

- सामान्य विमान टाइप रखरखाव और पायलट प्रशिक्षण लागत को इष्टतम बनाएंगे।

- विलय विदेशी वाहकों पर प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करेगा।

(घ) : भारत में हवाईअड्डों पर सीसीटीवी, एटीआरएस/एक्स-बीआईएस, डीएफएमडी, एचएचएमडी और ईटीडी आदि जैसे सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। कुछ प्रमुख हवाईअड्डे उन्नत सुरक्षा प्रणालियों और उपकरणों जैसे डुअल व्यू एक्सबीआईएस, बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, कतार प्रबंधन प्रणाली, एटीआरएस (ऑटोमोटिव ट्रे रिट्रीवल सिस्टम), पीआईडीएस (पैरीमीटर घुसपैठ पहचान प्रणाली), रिमोट स्क्रीनिंग और डिजी यात्रा- चेहरे से पहचान आधारित पहुँच से सुसज्जित हैं। बीसीएएस के नेतृत्व वाली समिति द्वारा किए गए सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण के आधार पर हवाईअड्डों पर सीआईएसएफ जनशक्ति में वृद्धि की जाती है।

ड) : विमानन प्रशिक्षण की आवश्यकता को पूरा करने, कौशल विकास को प्रोत्साहित करने और घरेलू प्रशिक्षण क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) देश में प्रशिक्षित पायलटों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने एक उदारीकृत उड़ान प्रशिक्षण संगठन (एफटीओ) नीति आरंभ की है, जिसके तहत

हवाईअड्डा रॉयल्टी (एफटीओ द्वारा एएआई को राजस्व हिस्सेदारी का भुगतान) की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है और भूमि किराये को काफी हद तक तर्कसंगत बनाया गया है।

(ii) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने छात्रों में नागर विमानन में रुचि पैदा करने के उद्देश्य से इंटरशिप योजना "प्रदीप्ति" आरंभ की है। इस योजना के उद्देश्य हैं:

- सैद्धांतिक ज्ञान के साथ व्यावहारिक संचालन/कार्यकलापों को जोड़ना।
- छात्रों को एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और गणित) / गैर-एसटीईएम डोमेन में अनुभव प्रदान करना - क्षेत्र को व्यापक बनाना।
- नागर विमानन से संबंधित छोटी अवधि की परियोजनाओं पर काम करने का अवसर प्रदान करना।

(च) और (छ) : वर्ष 2016 में, सरकार ने राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (एनसीएपी 2016) जारी की, जिसमें विमानन मूल्य क्रम के 20 से अधिक पहलुओं को शामिल करके प्रमुख कार्रवाई कदमों की परिकल्पना की गई है, जिनमें शामिल हैं: क्षेत्रीय संपर्क, संरक्षा, सुरक्षा, एयरलाइनें, हवाईअड्डे, द्विपक्षीय यातायात अधिकार, कोड-शेयर समझौते, एअर नेविगेशन, हेलीकॉप्टर, कार्गो, विनिर्माण, रखरखाव और कौशल विकास आदि। सरकार उड़ान को किफायती, सुविधाजनक बनाकर आम जनता तक पहुंचाने के लिए ठोस कदम उठा रही है और यात्रियों के लिए संरक्षित, सुरक्षित, किफायती और टिकाऊ हवाई यात्रा के साथ-साथ भारत और दुनिया के विभिन्न हिस्सों तक पहुँच के साथ कार्गो का हवाई परिवहन प्रदान कर रही है और एक एकीकृत इको-सिस्टम स्थापित कर रही है, जिससे नागर विमानन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है।

भारत की योजना स्थापित विमानन केंद्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए वर्ष 2030 तक भारतीय यात्रियों के लिए पसंदीदा विमानन केंद्र और वर्ष 2047 तक वैश्विक विमानन केंद्र बनने की है। इस रणनीति में भारत की भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाया गया है और इसमें घरेलू वाहकों को मजबूत करके विदेशी वाहकों को सीमित करना शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय वाहकों की अंतर्राष्ट्रीय यातायात हिस्सेदारी में वृद्धि के साथ-साथ आई-टू-आई यातायात में वृद्धि होगी।